

The report now received from the Andaman and Nicobar Administration has revealed that no new Island had come into existence in that area and it was in fact a Wedge rock already in existence that was mistaken to be a new Island after people in that area had noticed certain eruptions.

2. The delay in making this statement modifying the earlier answer is on account of the fact that aerial reconnaissance of the area had to be done and the report had to be compared with the chart issued by the Marine Survey of India.

13-21 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till twenty minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at twenty-three past fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair].

MATTERS UNDER RULE 377

(i) The state of affairs in Jawaharlal Nehru University

श्री मनोराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय,

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इनका नाम रोज रोज आ जाता है।

श्री मनोराम बागड़ी : रोज कभी आ सकता है किसी एक का ? इनको बताइये कि हफ्ते में एक ही आया करता है, वह भी स्पीकर महोदय कुछ ऐसा कह देते हैं कि अक्सर, रेडियो वाले लिखते नहीं हैं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : भाज देंगे आपका, घबड़ाइये मत।

श्री मनोराम बागड़ी : आपकी सिफारिश है क्या ? कल तुम्हारे भादमी ने ही गलत-फहमी कर दी थी, किसी का नाम नहीं दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, 4 मई, 1981 को बहुत से संसद-सदस्यों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में व्याप्त तथा कथित भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा प्रशासकीय अव्यवस्था के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एक्ट के अन्तर्गत विजिटर जांच की मांग की है। संसद-सदस्यों ने उस हेतु एक ज्ञापन भी दिया है जिस पर 161 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। संसद के इतिहास में किसी एक सवाल पर शायद ही इतनी बड़ी संख्या में सांसदों ने एकमत हो इतने प्रभावकारी ढंग से अपने को व्यक्त किया हो।

नेहरू विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एक प्रमुख विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना एक नया शैक्षणिक आदर्श कायम करने के उद्देश्य से की गई थी और इस पर करोड़ों की धनराशि व्यय की जा चुकी है। बड़े खेद का विषय है कि कुछ भ्रष्ट तत्वों तथा अधिकारियों के कारण इस संस्था की दयनीय दशा हो गई है।

वर्तमान में विश्वविद्यालय की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि यूनिवर्सिटी कोर्ट की बैठक भी लगभग दो वर्ष बाद बुलाई गई और ऐक्ट के अन्तर्गत गठित उप वैधिक समितियों की भी सर्वथा उपेक्षा की जा रही है। विश्वविद्यालय में बार-बार हड़ताल हो रही है। विद्यार्थियों को पानी एवं बिजली भी उपलब्ध नहीं है। छात्रों एवं कर्मचारियों के बीच मुठभेड़ हो रही है, अध्यापकों के आवासों पर डैकतियां हो रही

[श्री मनी राम बागड़ी]

हैं और तनावपूर्ण स्थिति बनी है। एक छात्रा पर गोली चलाई गई तथा पुस्तकालय के ठीक सामने एक भ्रमजली लाश परसों पाई गई है।

संसद में अनेकों बार इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाये गये हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया है। अतः इस बात की नितांत आवश्यकता है कि सारे मामले की व्यापक एवं उचित जांच कराई जाये ताकि विश्व-विद्यालय परिसर में एक स्वस्थ एवं आदर्श शैक्षणिक वातावरण कायम हो सके।

(ii) Alleged repression of Loco running Staff and Steps to implement their demands

SHRI A.K. BALAN (Ottapalam): The Loco-running Staff agitation which is more than a month old has been called off. Violation of agreements, curtailment of privileges, denial of not only trade union rights but also fundamental rights and mass dismissals were the immediate provocations for the agitation. Such a situation prevailed all over the nine Zonal Railways.

The Railway Ministry never cared to redress the grievances of locomen through negotiation. Instead, they resorted to all sorts of punitive and repressive measures. The magnitude of victimisation, arrests and police repression was such that staff were scared even to move out of their homes. In Southern Railways alone there are 83 cases of forcible retirement after the age of 55 years, 30 removal from service in summary and arbitrary way. 14 penal transfers, 18 suspensions and 28 court cases besides a volume of chargesheets numbering about 409.

Considering the adamant and stiff attitude of the Railway Ministry, the All India Loco-running Staff Association went ahead by volunteering to call-off the agitation on three conditions, namely, incorporating 10 hours' duty in the hours of Employment Regulations, restoring status-quo-ante as on 31-12-1980 as regards victimisation, arrests and working systems fixing of date for discussion to settle agreed and pending matters.

Now, that the agitation has been called off, we hope that the Government and the Railway Ministry will come forward and stop victimisation and repression and concede the long-pending demands in the interest of maintaining industrial peace in Railways, which can only be ensured by mutual confidence and co-operation.

(iii) Need for amendment in the Indian Electricity (Supply) Act, 1948 to improve electricity services

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन): उपाध्यक्ष महोदय, इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 में यह कहा गया है कि समाज के सभी तबकों में विद्युत प्रदाय "रीजनेबल रेट्स" पर तथा विद्युत मंडलों को "नो प्राफिट नो लास" के आधार पर चलाया जाएगा। किन्तु इस कानून की भावना के विपरीत सरकार विद्युत उप-भोक्ताओं से 16 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के रूप में, विद्युत उत्पादन पर 2.25 पैसे प्रति-यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन एक्साइज ड्यूटी के रूप में तथा विद्युत ग्रहों के निर्माण, पावर ट्रांसमिशन, ग्रामीण विद्युतीकरण पर दिए जाने वाले ऋणों पर भारी मात्रा में रायल्टी, लीज चांजिज तथा व्याज बसूल करती है, जिससे जहाँ एक ओर देश में विद्युत की दरों में वृद्धि होने के कारण